BA Part II (Sub/Gen)

Dr. Chiranjeev Kr Thakur
Sociology

Lecture I

निर्धनता को दूर करने के उपाय (Solutions for Removing Poverty)

निर्धनता ऐसी समस्या है जिस पर अन्य समस्याएं भी आश्रित हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी भी देश में जैसे-जैसे आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होती है, वैसे-वैसे वहां के जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। समाज के विकास के साथ-साथ रोजगार के साधनों में भी विकास होता जाता है। भारत में आर्थिक विकास की प्रक्रिया भी अनवरत रूप से जारी है परन्तु जनसंख्या में हो रही अभूतपूर्व वृद्धि के कारण बेरोजगारी की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। फिर भारतीय आर्थिक विकास का लाभ कुछ चुने हुए संपन्न औद्योगिक घरानों एवं पूंजीपतियों को ही अधिक प्राप्त हो रहा है तथा निर्धन और भी अधिक निर्धन होता जा रहा है, संपन्नता एवं विपन्नता की खाई दिनोंदिन चौड़ी होती चली जा रही है।

भारत सरकार ने निर्धनता को कम करने के लिए स्वतंत्रता के उपरान्त विशेषकर तीन योजनाओं पर कार्य किया है-

(1) पंचवर्षीय योजनाएं = पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य थे

a) उद्योग और कृषि के उत्पादन में वृद्धि द्वारा गरीबी को कम करना

b) प्रत्येक क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना

c) आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण को रोकना

d) आय और संपत्ति में अंतर और असमानता को कम करना
e) संतुलित क्षेत्रीय विकास की उपलब्धि

2) राष्ट्रीय कार्यक्रम : राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना 1969 से ही कार्यान्वित की गयी। सर्वप्रथम 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसके बाद 1972-73 में कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसी वर्ष सरकार द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़े इस्पात के कारखाने (भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी) तथा खाद्यान्न के थोक व्यापार को भी अपने हाथों में ले लिया गया। यद्यपि यह उपाय समाजवादी सिद्ध हो सकते थे परन्तु वास्तव में इनका कोई अपेक्षित लाभ नहीं हुआ। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य ध्येय था बड़े उद्योगों द्वारा बैंकों के संसाधनों का निजी उपयोग करने से बचाना। परन्तु उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि निजी उद्योगों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों में कमी नहीं हुई है।

1971 में अनुसूचित बैंकों द्वारा दिया गया ऋण 1969 में दिए गए ऋण की तुलना में कई गुना बढ़ गया। यद्यपि यह सही है कि कृषि और छोटे उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि मिलती है परंतु बड़े उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण के बाद निजी उद्योगों में उसके संसाधनों का बड़ा भाग लगा रहा है।